



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1944 (श0)  
(सं0 पटना 358) पटना, सोमवार, 13 जून 2022

सं० 08/आरोप-01-38/2018 सा0प्र0-8481  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

30 मई 2022

श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1079/11 तत्कालीन भूमि-सुधार उप समाहर्ता फूलपरास-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोघरडीहा, मधुबनी के विरुद्ध सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-19971/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.09.2018 को पारित आदेश में नगर पंचायत घोघरडीहा, मधुबनी में बरती गयी अनियमितता के मामले में संबंधित दोषियों के विरुद्ध तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4629 दिनांक 28.08.2018 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक की अवधि में संचालित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितता संबंधी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र को पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया एवं विभागीय पत्रांक 638 दिनांक 15.01.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मरणोपरान्त श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 29.05.2019) समर्पित किया।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोघरडीहा, मधुबनी के पदस्थापन के दौरान विभिन्न योजनाओं में बरती गयी वित्तीय अनियमितता के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के अंकेक्षण दल द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया। साथ ही सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-19971/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.09.2018 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण वादी द्वारा अवमाननावाद दायर किये जाने संबंधी सूचना भी नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा दी गयी है। वर्णित स्थिति में मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापक-9365 दिनांक 12.07.2019 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

4. मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-179 दिनांक 15.03.2022 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध गठित कुल 14 आरोपों में से 13 आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। आरोप सं०-04 का पहला एवं दूसरा भाग आंशिक रूप से प्रमाणित तथा तीसरा,

चौथा एवं पाँचवा भाग प्रमाणित नहीं पाया गया। विभागीय पत्रांक-5134 दिनांक 04.04.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्रमाणित नहीं पाया गया विभागीय पत्रांक 5134 दिनांक 4.4.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री कुमार से अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन की माँग की गयी, जिसके क्रम में श्री कुमार द्वारा अपना अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

5. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उक्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उन तथ्यों का उल्लेख विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बचाव बयान में भी किया गया था, जिसके समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०-04 के प्रथम एवं दूसरा भाग को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है, अन्य सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा विश्लेषण एवं जाँच परिणाम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि :-

प्रथम भाग :-निविदा सूचना में सोलर लाइट की विशिष्टियों एवं शर्तों का उल्लेख नहीं होने से संबंधित है। आरोपित पदाधिकारी ने इस संबंध में यह समर्पित किया था कि निविदा सूचना सं०-1/2011-12 (ज्ञापांक-171 दिनांक 02.07.2011) में विशिष्टियाँ एवं शर्तों का उल्लेख है, परन्तु प्रशासी विभाग का कहना है कि सोलर लाइट के विशिष्टियों का उल्लेख नहीं है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित कथन एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि निविदा सूचना सं०-1/2011-12 (ज्ञापांक-171 दिनांक 02.07.2011) में शर्तों का तो उल्लेख है, परन्तु सोलर लाइट के विशिष्टियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अतः चौथे आरोप के पाँच भागों में से यह भाग आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतीत होता है।

दूसरा भाग :-तुलनात्मक विवरणी के आधार पर कम दर वाले को आपूर्ति आदेश न देकर अधिक दर वाले निविदादाता को आपूर्ति आदेश देने से संबंधित है। इस पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव बयान पर विभागीय मंतव्य में तुलनात्मक विवरणी निविदा में उल्लिखित शर्तों के आलोक में सही ढंग से तैयार एवं निष्पादन नहीं करने का मंतव्य दिया गया है। साथ में ही न्यूनतम निविदादाता को अयोग्य करार दिये जाने के पश्चात द्वितीय निविदादाता से दर वार्ता नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं देना तथा मार्केट सर्वे के आधार पर मार्केट रेट के निर्धारण का कोई उल्लेख नहीं करने का मंतव्य दिया है। आरोपित पदाधिकारी ने इस मंतव्य पर अपनी प्रतिक्रिया समर्पित की कि कुल पाँच एजेंसी के तरफ से निविदा में भाग लिया गया था। न्यूनतम निविदादाताकर्ता एस०पी०ट्रेडिंग एवं कंसल्टेंट, साकची, झारखण्ड एवं Cipil Technology, Lalbagh, Darbhanga द्वारा निर्धारित अहर्ता के अनुरूप पाँच हजार अग्रधन राशि जमा नहीं करायी गयी। तब बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के आलोक में ही मे० गणेश ट्रेडर्स को तत्कालीन अध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत कार्यहित को देखते हुए सोलर लाइट लगाने का निदेश दिया गया था। आरोपित पदाधिकारी का यह भी कहना है कि यदि न्यूनतम दर अंकित करने वाली एजेंसी द्वारा शर्तों के अनुरूप यदि अग्रधन की राशि जमा करायी गयी होती, तो किसी भी स्थिति में मे० गणेश ट्रेडर्स को सोलर लाइट लगाने का कार्यदेश निर्गत नहीं किया जाता। आरोपित पदाधिकारी ने यह भी समर्पित किया कि उनके द्वारा सोलर लाइट के अधिष्ठापन हेतु कार्य में नियमों के अनुरूप ही प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित साक्ष्य, अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अग्रधन राशि जमा नहीं किये जाने के कारण ही न्यूनतम दर वाले निविदादाता को सोलर लाइट की आपूर्ति हेतु आदेश नहीं दिया गया था। यह निर्णय सही था, परन्तु आरोपित पदाधिकारी को मे० गणेश ट्रेडर्स से दर वार्ता करनी चाहिए थी, जो साक्ष्य एवं आरोपित पदाधिकारी के कथन के अनुसार नहीं की गयी प्रतीत होता है। अतः चौथे आरोप के पाँच भागों में से यह भाग आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतीत होता है।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1079/11, तत्कालीन भूमि-सुधार उप समाहर्ता फूलपरास-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोघरडीहा, मधुबनी का अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड उन्हें अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (वर्ष-2011-12 एवं 2012-13)

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मो० सिराजुद्दीन अंसारी,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 358-571+10-डी०टी०पी०

Website: <http://egazette.bih.nic.in>